एमएसएमई को बढ़ावा देने पर चीन होगा फेल : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पांच लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को 51 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण का बुधवार को शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं ने कभी हताशा, निराशा और अराजकता का शिकार रहे उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर में उत्साह व आत्मविश्वास का संचार किया है। इन योजनाओं की बदौलत एमएसएमई सेक्टर ने उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। पिछले पौने सात वर्षों में उप्र छठे और सातवें स्थान से देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले एक दशक में हमें उप्र को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। यदि एमएसएमई सेक्टर को उत्पादों की पैकेजिंग, डिजाइनिंग और मार्केटिंग में समुचित सहयोग दिया गया तो उत्तर प्रदेश के उत्पादों के आगे चीन भी फेल हो जाएगा

लोकभवन के सभागार में एमएसएमई विभाग की ओर से आयोजित मेगा ऋण वितरण समारोह में योगी ने कहा कि हस्तशिल्पियों व एमएसएमई उद्यमियों ने प्रदेश के निर्यात को तीन गुणा बढ़ाया है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर वोकल फार लोकल के अभियान पर मुहर लगाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। हम लकीर के फकीर नहीं बने। हमने कुछ नया दिया है, लेकिन हमें इससे संतोष नहीं करना चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को नई उड़ान देनी है। हर जिले के उत्पाद का डाक टिकट भी जारी होना चाहिए। इन उत्पादों की ग्रेडिंग होनी चाहिए। यह हमें वैश्विक पहचान दिलाएगा। एमएसएमई सेक्टर को लोन देने में बैंकर्स को उदारता

लोक भवन में मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में बोलते मुख्यमंत्री योगी • जागरण

- एक दशक में उप्र को बनाएंगे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- सीएम ने 51 हजार करोड़ रुपये ऋण वितरण का किया शुभारंभ

दिखाने का आह्वान करते हुए योगी ने कहा कि छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं है। पिछले पौने सात वर्षों में उत्तर प्रदेश के ऋण जमा अनुपात को 44-45 प्रतिशत से बढ़कर 56-57 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का आभार जताया, लेकिन यह भी कहा कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हमें इसे 60 प्रतिशत तक पहुंचाना है और फिर इसे 65 प्रतिशत तक लेकर जाना है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से 10 उद्यमियों को ऋण के तौर पर दी गई धनराशि के चेक सौंपे। मुख्यमंत्री ने मथुरा, सीतापुर, मेरठ और अमरोहा में प्लेज (प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फार डेवलपमेंट आफ ग्रोथ इंजिन्स) योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले निजी औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं को सहायता राशि के चेक भी दिए। ओडीओपी योजना के अंतर्गत संभल, सहारनपुर और मुरादाबाद में विकसित किए गए सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) का लोकार्पण किया।

संबंधित खबर >> 5